



उन्नति 2024

स्रोत: पी.आई.बी.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र के राज्यों में उद्योगों के विकास और रोजगार सृजन के लिये उत्तर-पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकीकरण योजना (Uttar Purva Transformative Industrialization Scheme- UNNATI), 2024 को मंजूरी दी।

उन्नति 2024 क्या है?

■ उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य उत्तर-पूर्व क्षेत्र के राज्यों में उद्योगों का विकास और रोजगार सृजन करना है।
- यह सीमेंट और प्लास्टिक जैसे पर्यावरणीय रूप से हानिकारक क्षेत्रों को प्रतबंधित करते हुए नविश को आकर्षित करने, मौजूदा नविशों का पोषण करने तथा नवीकरणीय/अक्षय ऊर्जा एवं इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों जैसे उद्योगों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

■ प्रमुख विशेषताएँ:

- योजना अवधि: यह योजना अधिसूचना की तथिसे 8 वर्ष की प्रतबंधित देनदारियों के साथ 31.03.2034 तक प्रभावी रहेगी।
 - योजना की पूरी लागत रुपए **10,037 करोड़** जिससे प्रतबंधित देनदारियों के लिये दस वर्षों एवं अतिरिक्त आठ वर्षों में वभिजति कथिा गया है।
- उत्पादन की शुरुआत: सभी पात्र औद्योगिक इकाइयों को पंजीकरण के अनुदान से 4 वर्ष के भीतर अपना उत्पादन या संचालन शुरू करना होगा।
- ज़ोन वर्गीकरण: प्रोत्साहन के लिये ज़िलों को **ज़ोन A** (औद्योगिक रूप से उन्नत) तथा **ज़ोन B** (औद्योगिक रूप से पछिड़ा) में वर्गीकृत कथिा गया है।
- नधिआवंटन: भाग A परवियय का 60% 8 पूर्वोत्तर राज्यों के लिये नरिधारति कथिा गया है और 40% फर्स्ट-इन-फर्स्ट-आउट (FIFO) आधार पर आवंटति कथिा गया है।

■ नविशकों के लिये प्रोत्साहन: यह योजना नविशकों को नई इकाइयाँ स्थापति करने अथवा वर्तमान इकाइयों का वसितार करने हेतु GST प्रयोज्यता के आधार पर वर्गीकृत वभिनिं प्रोत्साहन प्रदान करती है, जैसे:

- पूंजी नविश प्रोत्साहन
- केंद्रीय पूंजी ब्याज अनुदान
- GST के शुद्ध भुगतान से जुड़ी नई इकाइयों के लिये वनिरिमाण एवं सेवा से जुड़े प्रोत्साहन (MSLI), ज़ोन के आधार पर ऊपरी सीमा के साथ।

■ कार्यान्वयन रणनीति: उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन वभिग राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय समतियों की देखरेख में राज्यों के सहयोग से योजना को लागू करेगा।



उत्तर-पूर्व क्षेत्र के राज्यों से संबंधित अन्य सरकारी पहल क्या हैं?

- **उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिये प्रधानमंत्री विकास पहल योजना:** केंद्रीय बजट सत्र 2022-2023 में शुरू की गई और अक्टूबर 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित, पीएम-डिवाइन (PM-DevINE) का लक्ष्य पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) में बुनियादी ढाँचे तथा सामाजिक विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करना है।)
- **एडवांसिंग नॉर्थ ईस्ट पोर्टल:** यह NEC द्वारा नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन (NEDFi) के माध्यम से विकसित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म और वेब-आधारित पहल है जो NER के युवाओं के लिये बहुत ज़रूरी ज्ञान तथा मार्गदर्शन प्रदान करता है।
- **उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना:** NESIDS 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसने सत्र 2022-23 से 2025-26 के लिये 8139.50 करोड़ रुपए का नवीनीकृत अनुमोदित परियोजना प्राप्त होता है।
 - इस योजना में दो घटक शामिल हैं: **NESIDS-रोड और NESIDS-अदर दैन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर (OTRI)**।
- **RCS-UDAN** (उड़ान को और अधिक कफायती बनाने के लिये) के तहत उत्तर पूर्व को प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में रखा गया है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. उत्तर-पूर्वी भारत में उपपलवर्षों की सीमा के आरपार आवाज़ाही, सीमा की पुलसिगि के सामने अनेक सुरक्षा चुनौतियों में से केवल एक है। भारत-म्याँमार सीमा के आरपार वर्तमान में आरंभ होने वाली वभिन्न चुनौतियों का परीक्षण कीजिये। साथ ही चुनौतियों का प्रतिरोध करने के कदमों पर भी चर्चा कीजिये। (2019)